



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2014/माघ 14, 1935

No. 52]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2014/MAGHA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2014

सं. 3/2014-सेवा कर

सा.का.नि. 74(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि एक वायदा अनुबंध के संबंध में किसी पंजीकृत संगठन या किसी मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्य के उप दलालों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (इसके पश्चात् 'द फाइनेंस एक्ट' के रूप में संदर्भित) की धारा 66 के अंतर्गत सेवा कर का उद्ग्रहण (उसके गैर उद्ग्रहण सहित) संबंधी एक अभिक्रिया आम तौर पर प्रचलित थी और यह कि ऐसी सेवाएं वित्त अधिनियम के अंतर्गत सेवा कर के प्रति दायी थीं, जो कि सितम्बर 2004 की 10वीं तिथि से लेकर जून 2012 की 30वीं को तिथि समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त अभिक्रिया के अनुसार उद्ग्रहित नहीं की जा रही थी;

अतः, अब, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निदेश देती है कि एक वायदा अनुबंध के संबंध में किसी पंजीकृत संगठन या किसी मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्य के उप दलालों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर देय सेवाकर हेतु, उक्त अभिक्रिया के अनुसरण में उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसी कराधान सेवा जिस पर सेवाकर उद्ग्रहित नहीं किया जा रहा था, के संबंध में भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 354/131/2013-टी आर यू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2014

No. 3/2014-Service Tax

G.S.R. 74(E).— Whereas, the Central Government is satisfied that a practice was generally prevalent regarding levy of service tax (including non-levy thereof), under section 66 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as ‘the Finance Act’), on services provided by a authorised person or sub-broker to the member of a recognised association or a registered association, in relation to a forward contract, and that such services were liable to service tax under the Finance Act, which was not being levied according to the said practice during the period commencing from the 10th day of September 2004 and ending with the 30th day of June 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, the Central Government hereby directs that the service tax payable on the services provided by a authorised person or sub-broker to the member of a recognised association or a registered association, in relation to a forward contract, shall not be required to be paid in respect of such taxable service on which the service tax was not being levied during the aforesaid period in accordance with the said practice.

[F. No. 354/131/2013 - TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.